Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 7.384
Volume - 8, Issue - 9, September - 2025

DOIs:10.2018/SS/202509009 --:-- Research Paper / Article / Review

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं स्कूली शिक्षा: एक विश्लेषण

[1] डॉ. महेश कुमार चौधे [2] डॉ. संजय कुमार

[1] सहायक आचार्य, डी.एस.एम.एन.आर. यूनिवर्सिटी लखनऊ

[2] सहायक आचार्य, डी.एस.एम.एन.आर. यूनिवर्सिटी लखनऊ

[1] nimhmahesh@gmail.com [2] sanj.70@gmail.com

सार: *भारत मे शिक्षा सभी व्यक्ति का मूल अधिकार है। शिक्षा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा को मूलतः दो स्तर, स्कूली स्तर एवं उच्च पर विभजित किया जा सकता है। इन दोनों मे से स्कूली शिक्षा को मील के पत्थर के रूप मे देखा जाता है। किसी भी देश में व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकता को पूरा करने तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा मे बने रहने के लिए स्कूली शिक्षा का समसामयिक होना आवश्यक होता है। इन्ही तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार किया गया है। यह नीति देश में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में बदलाव लाने के साथ हीं एक विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह शिक्षा नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह नीति बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, और तकनीकी दृष्टिकोण से सशक्त शिक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्कूली शिक्षा में किए गए सुधारों के माध्यम से यह नीति बच्चों के समग्र विकास के बढ़ावा पर विशेष बल देता है। यह नीति न केवल ज्ञान बल्कि कौशल और मूल्य आधारित शिक्षा पर भी जोर देती है।*

मुख्य शब्द: *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एन.ई.पी., स्कूली शिक्षा, 21वीं सदी, समावेशी, उच्च शिक्षा।*

1. परिचय :

शिक्षा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति, समाज, एवं देश की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा के विभिन घटकों में भी परिवर्तन लजमी है। हमारे भारत जैसे विशाल देश में भी व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकता को पूरा करने तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा मे बने रहने के लिए स्कूली शिक्षा में अमुलचूर परिवर्तन की आवश्यकता थी। इन्ही शैक्षिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020), एक व्यापक दस्तावेज़ के रूप में प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारतीय स्कूली शिक्षा के साथ-साथ उच्चस्तरीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, समावेशी, और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। यह नीति देश में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में बदलाव लाने के साथ हीं एक विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह शिक्षा नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें विशेष रूप से स्कूल शिक्षा को एक मजबूत आधार देने की योजना बनाई गई है, ताकि भारतीय विद्यार्थी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें और उनके भीतर रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच के साथ-साथ उनका समग्र व्यक्तित्व का विकास हो सके।

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए समय - समय पर कई नीतियाँ बनी है। इन नीतियों मे से सबसे नवीनतम शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) है। इस शिक्षा नीति को भारतीय शिक्षा प्रणाली

में एक बड़ा बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इस नीति का उद्देश्य भारतीय बच्चों को वैश्विक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, ताकि वे न केवल देश में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धी बन सकें। वर्ष 2020 में प्रस्तुत इस नीति में विशेष रूप से स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की योजनाओं का उल्लेख किया गया है। इस नीति में शिक्षा के ढांचे को सुधार करने के साथ-साथ समग्र शिक्षा तथा बच्चों के समग्र विकास पर विशेष बाल दिया गया है। यह नीति भारत में शिक्षा के भविष्य को नए दृष्टिकोण से आकार देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। यह नीति भारत में पिछले चार दशकों में बने सभी शिक्षा नीतियों का पुनः मूल्यांकन करने के बाद तैयार किया गया है। यह शिक्षा नीति, शिक्षा के सभी स्तरों - प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक - में सुधार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख उद्देश्य:

- **सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा**: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक बच्चे को उत्कृष्ट शिक्षा का समान अवसर प्राप्त हो।
- **समानता और समावेशिता**: सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों के समावेशन के लिए विशेष उपाय किए गया हैं।
- **शिक्षा में तकनीकी सुधार**: डिजिटल और तकनीकी शिक्षा को प्रमुख रूप से प्रोत्साहित किया गया है।
- **बहुविकल्पीय शिक्षा और कौशल विकास**: छात्रों को उनके रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप शिक्षा देने की प्रणाली पर विशेष बाल दिया गया है।
- **भाषा नीति का पुनः निर्धारण**: मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है।

3. स्कूल शिक्षा में सुधार का दृष्टिकोण

स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और संरचना में सुधार के लिए NEP 2020 में कई महत्वपूर्ण बदलावों को प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान मे चल रही 10+2 स्कूली शिक्षा प्रणाली को बदलते हुए अब इसे 5+3+3+4 संरचना में विभाजित किया गया है। इस संरचना के तहत, बच्चों की शिक्षा की शुरुआत पहले से अधिक व्यवस्थित और सुलभ तरीके से करने पर बाल दिया गया है।

5+3+3+4 शिक्षा संरचना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पारंपरिक 10+2 संरचना को बदलकर **5+3+3+4** संरचना को अपनाए जाने पर बल दिया गया है। इस संरचना में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई)नको शामिल किया गया है। इस संरचना का उल्लेख निम्नलिखित है :

- इस शिक्षा नीति मे 3 वर्ष अर्थात 3-6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई)नको शामिल किया गया है। इसमें आंगनवाड़ी, प्री स्कूल एवं वलवाटिक शामिल है।
- **5 वर्ष - पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा (3-8 वर्ष):** इस चरण में 3-8 वर्ष तक के बच्चों को प्रथम 3 वर्ष अर्थात 3-6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) को शामिल किया गया है। इसमें आंगनवाड़ी, प्री स्कूल एवं वलवाटिक शामिल है। इसके उपरांत 2 वर्ष की शिक्षा अर्थात कक्षा 1 से कक्षा 2 तक की प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख किया गया है। इस चरण में बच्चों को सरल भाषा, गणित, विज्ञान, और सामाजिक अध्ययन के बुनियादी पहलुओं की शिक्षा पर बाल दिया गया है।

- **3 वर्ष - प्राथमिक शिक्षा (8-11 वर्ष)**: इस चरण में 8-11 वर्ष तक के बच्चों को कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की शिक्षा का उल्लेख किया गया है। इस चरण में विद्यार्थियों को और गहरे विषयों की जानकारी दी जाएगी, लेकिन यह ध्यान रखा जाएगा कि बच्चे मानसिक रूप से तैयार हैं।
- **3 वर्ष - माध्यमिक शिक्षा (11-14 वर्ष)**: इस चरण में 11-14 वर्ष तक के बच्चों को कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों को उच्च-स्तरीय शिक्षा प्रदान कोला का उल्लेख किया गया है। इस स्तर पर विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों के विकल्पों की स्वतंत्रता मिलेगी।
- **4 वर्ष - उच्च माध्यमिक शिक्षा (14-18 वर्ष)**: इस चरण में 14-18 वर्ष तक के बच्चों को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों को उच्च-स्तरीय शिक्षा प्रदान का उल्लेख किया गया है। इस स्तर पर विद्यार्थी अपने विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकेंगे और विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश कर सकेंगे।

यह संरचना बच्चों की मानसिक और बौद्धिक विकास के अनुरूप माना जाता है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा का प्रत्येक चरण बच्चों के विकास में सहायक हो।

मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह सुझाव दिया गया है कि छात्रों को उनके **मातृभाषा** या स्थानीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा दी जाए। इसे शिक्षा के गुणात्मक स्तर को बढ़ाने के रूप में देखा गया है। प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की समझ को बेहतर बनाने के लिए यह नीति एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

कई अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शोधों में भी यह पाया गया है कि जो बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनकी समझ अधिक बेहतर होती है। इससे बच्चों को सीखने में आसानी होती है और वे ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं। नीति के अनुसार, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।

शिक्षा में तकनीकी सुधार और डिजिटल शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में डिजिटल शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत सहित पूरे विश्व में ऑनलाइन शिक्षा का महत्व और प्रभाव अधिक स्पष्ट हुआ है। । इसी को ध्यान में रखते हुए, इस नीति में यह सुनिश्चित किया गया है कि शिक्षा में तकनीकी संसाधनों का उपयोग शिक्षण ऐवन प्रशिक्षण में अधिक स्व अधिक किया जाए। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विवहीं मत्वपूर्ण कदम जैसे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का निर्माण, ई-लर्निंग और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की पेशकश तथा टेक्नोलॉजी और डिजिटल सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों की रुचि और सीखने के तरीके को सुधारने की योजना आदि मत्वपूर्ण विंदुओं पर विशेष बल दिया गया है। एनसीईआरटी (NCERT) और एनआईओएस (NIOS) जैसी संस्थाएँ डिजिटल पाठ्यक्रमों और कंटेंट को उपलब्ध कराने में मदद करेंगी। इसके साथ ही, नीति में यह भी कहा गया है कि डिजिटल डिवाइड को खत्म किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर विद्यार्थी को डिजिटल संसाधनों तक समान पहुँच हो।

समावेशी शिक्षा: विशेष वर्गों का ध्यान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली स्तर पर समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। इसमें विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों, वंचित समुदायों और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों पर ध्यान आकर्षित किया गया है। शिक्षा के किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर मिले। समावेशी शिक्षा के लिए कई विशेष योजनाएं बनए जाने पर बल दिया गया है। इनमें से विशेष शिक्षा के लिए संसाधन अर्थात दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष कक्षाएँ और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जाना तथा अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के लिए शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के प्रयास पर विशेष बल दिया गया है।

शिक्षक प्रशिक्षण और सुधार

एन ई पी 2020 में शिक्षकों की भूमिका को अहम माना गया है। यही कारण है कि इस नीति में शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस नीति में यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है कि शिक्षक न केवल अपनी विषय-विशेष जानकारी में सुधार करें, बल्कि उन्हें बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाने पर बल दिया गया है। इसके अलावा, शिक्षक के चयन प्रक्रिया में सुधार किए जाने के साथ-साथ केवल योग्य और प्रेरित शिक्षक को ही शिक्षा क्षेत्र में काम करने के अवसर पर विशेष बल दिया गया है।

मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा में सुधार के साथ-साथ मूल्यांकन प्रणाली में भी बदलाव करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में, भारतीय शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन केवल परीक्षा आधारित होता है। एन ई पी 2020 में मूल्यांकन प्रणाली को बदलने की योजना पर ध्यान आकर्षित किया गया है। इस यजना के अनुसार विद्यार्थियों के समझ और कौशल को प्राथमिकता दी जाएगी, न कि केवल उत्तरी उत्तरात्मक परीक्षाओं पर। इसमें परियोजना आधारित मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन, और फॉर्मेटिव मूल्यांकन को बढ़ावा दिया गया है।

4. निष्कर्ष:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक नई दिशा देने का प्रयास किया गया है। यह नीति बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, और तकनीकी दृष्टिकोण से सशक्त शिक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्कूली शिक्षा में किए गए सुधारों के माध्यम से यह नीति बच्चों के समग्र विकास के बढ़ावा पर विशेष बल देता है। यह नीति न केवल ज्ञान बल्कि कौशल और मूल्य आधारित शिक्षा पर भी जोर देती है। यदि इस नीति को सही तरीके से लागू किया जाता है, तो यह भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक नई ऊँचाई तक पहुंचा सकती है। भारत में एक समग्र, बहुस्तरीय, और समावेशी शिक्षा प्रणाली की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने मे मील के पत्थर के तरह काम करेगी ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- द इंटरनेशनल कमीशन ऑन एज्यूकेशन फॉर द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी, यूनेस्को(1996): लर्निंग: द ट्रेजर विदिन यूनेस्को।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020), भारत सरकार ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), भारत सरकार ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992), संशोधित, भारत सरकार ।
- www.education.gov.in